



मोदी का पुनःप्रधानमंत्री बनना आसान नहीं

शिमला/शैल। सातवें चरण के मतदान के साथ ही चुनावी प्रक्रिया का एक सबसे बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है। अब केवल मतगणना और उसका परिणाम शेष है। अन्तिम चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह ने पार्टी मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपने ही मन की बात इस वार्ता में रखी क्योंकि उन्होंने पत्रकारों का एक भी सवाल नहीं लिया और जब सवाल ही नहीं लिया तो जवाब का प्रश्न ही नहीं उठा। हां इस पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री ने देश की जनता का धन्यवाद किया और दावा किया कि वह पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापिस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दावा कितना पूरा होता है यह परिणाम आने पर ही पता लगेगा। लेकिन इस वार्ता में जिस तरह से प्रधानमंत्री को प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे को देशभक्त बताने वाले ब्यान पर निरुत्तर होना पड़ा है। उससे भाजपा का जो चेहरा देश के सामने आया है उसने पूरे चुनाव और उसके परिणामों पर एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। इस पृष्ठभूमि में यदि पूरे चुनाव का आकलन किया जाये तो सबसे पहले यह सामने आता है कि चुनाव भाजपा में केवल दो व्यक्तियों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष के गिर्द ही केन्द्रित रहा है। इसी के साथ यह भी सामने आया है कि इस चुनाव में पार्टी ने प्रिन्ट मीडिया की बजाये सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर ज्यादा निर्भरता रखी। तीसरा तथ्य यह रहा है कि भाजपा ने चुनाव में आम आदमी के मुद्दों बेरोजगारी, मंहगाई और भ्रष्टाचार को अपने प्रचार में कहीं भी केन्द्र में नहीं आने दिया। भाजपा के एक भी स्टार प्रचारक ने इन मुद्दों पर न तो अपने चुनावी भाषणों में और न ही पत्रकार वार्ताओं में चर्चा में आने दिया। जबकि कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा अपने को केन्द्रित रखा। भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में भी इन मुद्दों को प्रमुखता नहीं दी गयी है। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र का केन्द्र बिन्दु ही यही मुद्दे हैं। भाजपा हर चरण के साथ मुद्दे बदलती रही है और अन्त तक आते-आते उसने विपक्ष की गालियों की गिनती भी जनता के सामने मुद्दा बनाकर पेश कर दिया। इस चुनाव में प्रधानमंत्री

ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कारवाई, राष्ट्रवाद और प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर “भगवा आतंकवाद” के सम्बोधन को मुद्दा बनाकर हिन्दुवोटों का धुवीकरण करने के प्रयास के गिर्द ही पूरे चुनाव प्रचार को केन्द्रित रखा है। इसलिये यह आकलन करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस धुवीकरण का अन्तिम परिणाम क्या हो सकता है।

इसी धुवीकरण का आकलन करने से पहले 2014 के चुनावों से लेकर अब तक के घटनाक्रमों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। 2014 के चुनावों से पहले कालेधन और भ्रष्टाचार को लेकर जो जनधारणा रामदेव और अन्ना हजारे के आन्दोलनों के माध्यम से तैयार हुई थी उसका सबसे अधिक लाभ

भाजपा को मिला था क्योंकि इस जनधारणा को ‘अच्छे दिनों’ का भरोसा दिखाया गया था। लेकिन आज न तो अच्छे दिन ही आये हैं



और न ही रामदेव और अन्ना के आन्दोलन हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा को

हरियाणा, उत्तराखण्ड और हिमाचल को छोड़कर कहीं भी अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। जहां भी भाजपा ने सरकारें बनायी हैं वहां

चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन बनाये गये और तब सरकारें बनीं। बिहार में लालू-नितिश के गठबंधन को तोड़कर भाजपा-नितिश गठबंधन सत्ता में आया। उत्तर प्रदेश में हिन्दु-मुस्लिम धुवीकरण से प्रदेश में सरकार बनी लेकिन जैसे ही इस धुवीकरण की राजनीति को समझकर सपा-बसपा एक हुए वैसे ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव भाजपा हार गयी। 2014 के बाद लोकसभा का हर उपचुनाव भाजपा हारी है यह एक तथ्य है। इसके बाद गुजरात और कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति सुधरी। कर्नाटक में तो जेडी(एस)

और कांग्रेस ने सरकार बना ली। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें भाजपा के हाथ से निकल गयीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 2014 के चुनावों के बाद से मतदाता लगातार भाजपा से दूर होता गया है।

भाजपा का बड़ा शक्ति केन्द्र आरएसएस है। क्योंकि भाजपा संघ परिवार की एक राजनीतिक ईकाई है। संघ का पूरा विचार-दर्शन हिन्दुत्व के गिर्द केन्द्रित है यह सब जानते हैं। इस विचार-दर्शन की सफलता के लिये संघ के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गृहस्थी तक नहीं बसाई है। मुस्लिम समुदाय को लेकर संघ का अपना एक विशेष विचार दर्शन और धारणा है यह सब जानते हैं। इस धारणा से कितने सहमत भी हैं यह एक अलग प्रश्न है। लेकिन इस धारणा के प्रतीक रूप में सामने आये मुद्दे अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाना और मुस्लिमों

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या एग्जिट पोल मतदान के बाद एक घण्टे के भीतर सम्भव हैं?

शिमला/शैल। अन्तिम चरण का मतदान छः बजे तक चला और एग्जिट पोल के आंकड़े साढ़े छः आने शुरू हो गये। एक घण्टे से भी कम समय में मतदाताओं से संपर्क भी हो गया। उन्होंने यह भी बता दिया कि वह किसके पक्ष में वोट डालकर आये हैं। हिमाचल की चारों सीटों पर अन्तिम चरण में मतदान हुआ है लेकिन एग्जिट पोल हिमाचल का भी संभावित परिणाम आ गया। जो लोग हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं वह व्यवहारिक रूप में यह मानेंगे कि यदि यह सर्वेक्षण प्रदेश के चार शहरों शिमला, हमीरपुर, मण्डी और धर्मशाला में ही किया गया हो और पांच-पांच सौ लोगों से भी जानकारी ली गयी हो तो भी उस जानकारी को कम्पाईल करके और फिर पूरे प्रदेश पर उसका आकलन किसी परिणाम पर पहुंचने के लिये कम से कम एक दिन का समय लगता तथा इस काम के लिये सौ से अधिक लोगों को लगाया जाता और इसकी जानकारी तुरन्त खुफिया तन्त्र तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसी कोई

जानकारी प्रदेश भर से कहीं से भी नहीं आयी है। इसलिये यह व्यवहारिक रूप में ही संभव नहीं है कि मतदान के बाद एक घण्टे के भीतर यह सब कुछ हो पाता। ऐसा तभी संभव हो सकता है कि किसी ने मतदान से बहुत पहले ही यह सब कर रखा हो और इसकी जानकारी एग्जिट पोल ऐजेंसीयों तक पहुंचा दी हो।

एग्जिट पोल चुनाव आयोग द्वारा 2013-14 से ही प्रतिबन्धित हो चुके हैं क्योंकि इन सर्वेक्षणों से मतदाता की गोपनीयता भंग होती थी। मतदाता ने किसे वोट दिया है इस जानकारी को गोपनीय रखना उसका अधिकार है। जबकि एग्जिट पोल का अर्थ है कि जैसे ही मतदाता वोट डालकर मतदान केन्द्र से बाहर निकला तभी कुछ ही क्षणों में उससे संपर्क करके यह जानकारी हासिल कर ली जाये। लेकिन किसी भी मतदान के आसपास से इस तरह की जानकारी जुटाये जाने की जानकारी नहीं आयी है। इसलिये किसी भी गणित में ऐसा एग्जिट पोल हो पाना संभव नहीं है और जब

यह संभव ही नहीं है तो फिर इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वभाविक है।

इन एग्जिटपोल के नतीजे कितने प्रमाणिक हो सकते हैं इस पर इससे भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है कि आठ अलग-अलग एग्जिट पोल समाने आये हैं और इनके अपने ही परिणामों में सौ से अधिक सीटों का अन्तराल है एक पोल में भाजपा को 365 सीटें दी गयी है और दूसरे में 242 सीटें दी गयी हैं। हर पोल की अधिकतम और कम से कम सीटों में 30 से 50 तक अन्तर है। हिमाचल की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि यहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के भीतर उच्च स्तर पर भारी भीतरघात हुआ है। इस भीतरघात के कारण यहां के परिणाम एकदम अप्रत्याशित होंगे। यह तय है कि परिणाम आने के बाद दोनों दलों में इस भीतरघात के आरोप शीर्ष नेतृत्व तक खुलकर लगेंगे। प्रदेश की चारों सीटों पर कड़ा मुकाबला हुआ है। यह चुनाव एक तरह से

मोदी को लेकर जनमत संग्रह बन गया था। मतदान ने मोदी के पक्ष या उसके विरोध में वोट दिया है भाजपा ने यह धारणा पूरे देश में फैला दी थी। एग्जिट पोल भी उसी धारणा को पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन चुनावी आंकड़े हिमाचल के संदर्भ में इस धारणा को पुख्ता नहीं करते क्योंकि 2014 के मुकाबले 2017 में विधानसभा चुनावों में मत प्रतिशत बढ़ा लेकिन 2019 के चुनावों में 60 विधानसभा हल्कों में यह प्रतिशत घट गया है। जबकि केवल आठ में यह बढ़ा है जबकि कुल मिलाकर मतदान इस बार 7% बढ़ा है यह ठीक है कि यदि विधानसभा और लोकसभा में यह अन्तर रहता ही है। लेकिन जब 7% मतदान का आंकड़ा बढ़ा है तो यह दिखायी भी देना चाहिये था और इस नाते यह आंकड़ा विधानसभा के आसपास रहना चाहिये था। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में यह 2014 की बराबरी पर पहुंच गया है इससे यही लगता है कि मोदी के पक्ष में जिस लहर का दावा किया जा रहा था वह वास्तव में है ही नहीं और इससे मोदी की सत्ता में वासपी कठिन लगती है।

2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा एवं सहयोगी दलों को 2014 से अधिक सीटें मिलेंगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा एवं सहयोगी दलों को 2014 के लोकसभा चुनावों से

उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र में पुनः सत्तासीन बनाने के लिए युवा वर्ग एवं महिलाओं की भूमिका अहम होगी और उनमें नरेन्द्र मोदी को



भी अधिक सीटें मिलेंगी क्योंकि देश के लोग विगत पांच वर्षों में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व विकास से संतुष्ट हैं और विकास की इस गति को बिना किसी रूकावट के आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मण्डी के विधानसभा क्षेत्र नाचन के तहत जाछ में मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा के पक्ष में आयोजित एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

पुनः देश की कमान संभालने के लिए काफी जोश व उत्साह भी है। आज मतदाताओं की एक ही आवाज है कि देश की कमान मजबूत नेतृत्व के हाथ में संभाली जाएगी और वह नेतृत्व नरेन्द्र मोदी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा के साथ देश की जनता की सेवा की है और आज देश विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि

मोदी सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी एवं ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की गई हैं जो जनता के लिए वरदान साबित हो रही हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि नरेन्द्र मोदी प्रदेश के कोने कोने से परिचित हैं और वे प्रदेश की विकास आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी हिमाचल से विशेष स्नेह रखते हैं और उन्होंने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ों की सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास की गति नहीं थमनी चाहिए, इसके लिए पुनः नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के लिए जुझारू एवं कर्मठ नेता घोषित किए हैं। उन्होंने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि देश की बागडोर पुनः मजबूत नेतृत्व को संभालने के लिए चारों सीटों पर भाजपा को भारी मतों से जीत दिलाएं। इस अवसर पर नाचन के विधायक विनोद कुमार, मंडल अध्यक्ष रविन्द्र राणा एवं अन्य नेतागण उपस्थित थे।

माइक्रो टर्नर, रोक मैन इंडस्ट्रीज में 60 होनहार युवकों का चयन

शिमला/शैल। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 15 मई को हुए कैपस साक्षात्कार में माइक्रो टर्नर (बढ़ी) और रोक मैन इंडस्ट्रीज (लुधियाना) कंपनी ने 60 होनहार एवं प्रशिक्षित युवकों का चयनित किया है। ये कुछ चयनित युवक 20 और 25 मई तारीख के बीच में कंपनी के प्लांट बढ़ी और लुधियाना में जॉइनिंग देंगे। और कुछ युवक 6 जून तक जॉइनिंग देंगे। यह जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य ईएसके लखनपाल ने बताया कि सभी चयनित युवकों को बढ़ी प्लांट में आठ घंटे के 8100 रुपए मासिक और लुधियाना प्लांट में आठ घंटे के 8800 रुपए मासिक वजीफा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से एक टाइम का खाना, ईएसआई, पीएफ, यूनिफॉर्म, साल

की सात सीएल और सात नेशनल छुटियां मिलेंगी। उन्होंने सभी चयनित युवकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। कंपनी की ओर से कैपस साक्षात्कार लेने आए एचआर विभाग की बिरेदर कौर और सुरेश चौधरी ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में जो कैपस साक्षात्कार आयोजित हुआ उसमें 15 व्यवसायों के प्रशिक्षित युवकों ने अपना भाग्य आजमाया, जिनमें से 60 युवकों का चयन हुआ है। उधर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर संतोष नारायण ने बताया कि सभी चयनित युवाओं को जॉइनिंग के समय अपने समस्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लाने को कहा है। इस अवसर पर आईटीआई शाहपुर के अनुदेशक आशीष शर्मा और फतेह सिंह उपस्थित रहे।

मतदाताओं को मिलना चाहिए 6000 वोटरशिप भत्ता: कर्नल ठाकुर सिंह

शिमला/शैल। मंडी संसदीय क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी कर्नल ठाकुर सिंह ने कहा है कि मतदाताओं को कम से कम 6000 वोटरशिप भत्ता मिलना चाहिए। आजाद प्रत्याशी ने कहा कि सांसदों व विधायकों को यदि पेंशन मिल रही है तो वोटरों को भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक भरत गांधी ने इस योजना पर कार्य किया है और 30 वर्षों से मतदाताओं को वोटरशिप भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है लेकिन कोई भी सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। वे कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। हिमाचल सरकार फैक्टर एक के तहत एक गुणा मुआवजा दे रही है जोकि गलत है। मुम्बई हाई कोर्ट ने फैक्टर एक को गैर कानूनी कर दिया है। इसलिए अब फैक्टर तीन के तहत मुआवजा चार गुणा पूरे देश में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम विधायक व सांसदों को चुनते हैं तो वे वीआईपी श्रेणी में क्यों आते हैं और उन्हें वीआईपी सुविधा क्यों मिलती है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में 5 लाख 80 हजार वीआईपी हैं जो सारे हमारे

भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमेशा सर्वोपरि: सैजल

सोलन/शैल। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा का एक बार फिर से

कहा कि केन्द्र में तीसरे मोर्चे की सरकार के दौरान खुफिया तंत्र को खोखला कर



दिया गया था। यह किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब-जब कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों की सरकार केन्द्र में रही हमेशा देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि माना है।

सत्ता में आने का दावा करते हुए भाजपा नेता व मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि पूरे देश भर के लोग पसंद एवं संस्कृति से अलग-अलग हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में एकजुट हैं। उन्होंने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए

राजीव सैजल ने कहा कि कांग्रेस जो 55 साल में नहीं कर पाई वो मोदी नीत सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए पिछले पांच साल में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति देखी जाये तो देशभर के लोगों की पसंद एवं संस्कृति अलग-अलग है

लेकिन हर जगह एक बात समान है और वह है मोदी के पक्ष में पूरे देश का एक जुट होना।

उन्होंने कहा कि 'एक तरफ आपके पास मोदी हैं जिन्होंने कभी एक भी छुटी नहीं ली है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो लंबी छुटी के लिए अज्ञात स्थानों पर चले जाते हैं, जिसके बारे में उनकी मां को भी पता नहीं होता है।' उन्होंने कहा कि लोग 'ऐसे नेता की तलाश कर रहे हैं जो देश के प्रति अपना जीवन समर्पित करें न कि अपने परिवार का हित साधें।'

भाजपा नेता ने कहा कि 'मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो पांच साल में किया है वह कांग्रेस 55 साल में भी नहीं कर पाई।' उन्होंने भाजपा के केन्द्र में फिर से सत्ता में आने पर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी लागू करने की बात दोहराई।



उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य व शिक्षा हर एक का अधिकार है और वह सबको मुफ्त मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार जनता से रोड़ टैक्स ले रही है तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। हिमाचल की नदियां का पानी जब पंजाब हरियाणा में सिंचाई के लिये उपयोग में लाया जा सकता है तो इससे हिमाचल में जमीन को क्यूं नहीं सिंचा जा सकता। क्या उठाउ जल योजना द्वारा यह पानी सबको सिंचाई के लिए नहीं मिलना चाहिए।

खर्च पर चलते हैं और सरकार पर बोझ है। जबकि चीन में मात्र 400 वीआईपी हैं तभी उनका देश हम से आगे है। इसलिए वीआईपी की संख्या को घटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को ओआरओपी पूरी तरह नहीं दिया गया है, जोकि डेढ़ इंक्रीमेंट कम है इसका रिव्यू हर साल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम वीआईपी की संख्या घटाएंगे और सामूहिक संपत्ति जो सरकार व आम जनता की है का हिस्सा आम जनता को भी मिलना चाहिए। यह हिस्सा तभी मिलेगा जब हर वोटर को वोटरशिप भत्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि ब्राजील एनबीबिया और कुछ यूरोपियन देशों में मतदाताओं को वोटर भत्ता मिल रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वीआईपी के खर्चे कम होने चाहिए और विधायकों व सांसदों का वेतन व पेंशन भी बंद होनी चाहिए तभी हमारा देश खुशहाल होगा। क्योंकि यह सेवा है नौकरी नहीं। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से निजात के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए सरकारी अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त होना चाहिए।

23 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती: ऋग्वेद ठाकुर

शिमला/शैल। मंडी जिला में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के बाद अब प्रशासन ने मतगणना को लेकर चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 23 मई को मतगणना के लिए प्रशासन द्वारा समस्त प्रबन्ध मुकम्मल कर लिए गए हैं।

मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के उपरान्त सभी ईवीएम मशीनें सील करके कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग कक्षों में सुरक्षित रखी गई हैं। पुल्ना इंतजाम करते हुए ईवीएम की बहुस्तरीय सुरक्षा तय की गई है। केन्द्रीय सुरक्षा बल, राज्य आर्म्ड फोर्स तथा स्थानीय पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी के माध्यम से भी कड़ी निगरानी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान केवल अधिकृत लोगों को ही मतगणना स्थल के अंदर जाने की अनुमति होगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की

जाएगी। मतगणना केंद्र के समीप मीडियाकेंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मतगणना के समय यदि कोई ईवीएम किसी वजह से पोलिंग नहीं दर्शाती तो उस स्थिति में उस केंद्र की वीवीपैट की पर्चियों की गणना की जाएगी।

ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मतगणना 23 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी। जिला में तीन जगहों पर मतगणना की जाएगी। मंडी और सुन्दरनगर में चार-चार जबकि जोगिन्दरनगर में दो विधानसभा के मतों की गणना होगी। जिला के सभी पोस्टल मतों की गिनती मंडी में ही की जाएगी, जो निर्वाचन अधिकारी मंडी की देखरेख में होगी। राजकीय महाविद्यालय मंडी में सदर, बल्ह, धर्मपुर और सराज विधानसभा क्षेत्रों और सुन्दरनगर के जवाहरलाल इंजीनियरिंग कॉलेज में करसोग, नाचन, सुन्दरनगर और सरकाघाट जबकि राजकीय महाविद्यालय जोगिन्दरनगर में द्रंग और जोगिन्दरनगर विधानसभा क्षेत्रों

में डाले गए मतों की गणना की जाएगी।

मंडी स्थित वल्लभ कॉलेज के नए एवं पुराने भवन में दो सभागारों में चार विधानसभा क्षेत्रों में हुए वोटों की गिनती के लिए 40 टेबल लगाए गए हैं। जिनमें मंडी सदर के लिए 14, बल्ह और धर्मपुर के लिए 8-8 और सराज की मतगणना के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं। सुन्दरनगर के जवाहरलाल इंजीनियरिंग कॉलेज में चार विधानसभा क्षेत्रों में हुए वोटों की गिनती के लिए चार सभागारों में 50 टेबल लगाए गए हैं। जिनमें करसोग, नाचन और सुन्दरनगर के लिए 12-12 और सरकाघाट के लिए 14 टेबल हैं। राजकीय महाविद्यालय जोगिन्दरनगर के धरातल और प्रथम तल में स्थित सभागार में जोगिन्दरनगर और द्रंग को वोटों की गिनती के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 10-10 टेबल हैं। इस बार हर विधान सभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट और ईवीएम की मतगणना का मिलान किया जाएगा।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

शिमला में जलापूर्ति एवं गुणवत्ता की निगरानी कर रही है सरकार:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने शिमला में जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मई, 2018 के दृष्टिगत सरकार शिमला में जलापूर्ति एवं गुणवत्ता की निगरानी कर रही है, जिसके फलस्वरूप सम्बद्ध विभागों के साथ जलापूर्ति के लिए समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर के निवासियों को पहली बार प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जा रही है तथा नगर निगम के सभी वार्डों को समय

सारिणी के अनुसार 48 मिलियन लीटर सुनिश्चित की जा रही है।



से अधिक पानी की प्रतिदिन आपूर्ति

उन्होंने कहा कि जलापूर्ति में

आम नागरिकों को सामाजिक न्याय सुलभ बनाने का करें प्रयास:न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एवं प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्म

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि समाज में पनप रही कुरीतियों के खिलाफ लोगों का जागरूक करना है।



चन्द चौधरी ने न्यायिक प्रणाली से जुड़े सभी अधिकारियों से आम नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय सुलभ बनाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपायुक्त कार्यालय मंडी के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा राष्ट्रीय कानूनी सहायता मिशन केवल अदालत तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि

उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेश भर में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सदैव प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वचनबद्ध है जिनके द्वारा पात्र लोगों को समय पर प्रभावी ढंग से कानूनी सहायता प्रदान की जा सके, जो स्वयं इसका लाभ उठाने की स्थिति में न हों।

शिविर में मौजूद उपमण्डल

स्तरीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, पैनल अधिवक्ता, रिटेनर अधिवक्ता, रिमांड काउंसिलर एवं पैरा लिगल वालटियर्स से आह्वान किया कि वे कानूनी सहायता की जानकारी बारे लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें ताकि दूरदराज के पात्र लोग भी कानूनी सहायता से वंचित न रहें। उन्होंने कहा राष्ट्रीय कानूनी सहायता मिशन की सार्थकता की महत्ता तभी बन पाएगी जब आप अपने-अपने व्यवसाय को ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाएं और गरीब व असहाय लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहे।

इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.के.शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंस राज, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्पना शर्मा, सचिव जिला सेवा प्राधिकरण असलम बेग, बार एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश शर्मा, उपाध्यक्ष विख्यात गुलेरिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मानवता की सेवा के लिए रैडक्रॉस सोसायटी को उदारता से दान दें: डा.साधना ठाकुर

शिमला/शैल। अध्यक्षा, अस्पताल कल्याण शाखा डा. साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश रैडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की बैठक

कूपनों की बिक्री के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रैडक्रॉस समाजसेवी संस्था है जिसमें प्रत्येक



की अध्यक्षता की। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को मानवता की निःस्वार्थ सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश रैडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा को उदारता से दान देने का अनुरोध किया।

डा. साधना ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश रैडक्रॉस सोसायटी के सदस्यों को शत प्रतिशत

सदस्य की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी सदस्यों को समाज के निर्धन, बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा के लिए अपना सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष वार्षिक रैडक्रॉस मेला जून माह में शिमला के रिज मैदान में आयोजित

किया जाएगा। मेले में विभिन्न सरकारी स्कूलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा तम्बोला, फैंसी ड्रेस, बेबी शो, घुड़सवारी, स्किंग गेम, ऑरकेस्ट्रा, डॉग शो आदि अनेक मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मेले में पर्यटन विभाग द्वारा पारम्परिक हिमाचली भोजन तथा विभिन्न महिला संगठनों व सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न भारतीय व विदेशी खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए जाएंगे।

बैठक का संचालन अस्पताल कल्याण शाखा की अवैतनिक सचिव पूनम चौहान ने किया।

इस अवसर पर सचिव, राज्यपाल राकेश कंवर, चिकित्सा अधीक्षक इंदिरा गांधी मैडीकल कॉलेज एवं अस्पताल डॉ.जनक ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज भित्तल, कार्यकारी सचिव पी.एस.राणा तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और हिमाचल प्रदेश राज्य रैडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा के सदस्य उपस्थित थे।

वृद्धि गुम्मा पम्पिंग स्टेशन एवं जाखू, ढिगूधार, कामना देवी और नॉर्थओक के पुराने पंपों को बदले जाने के कारण हुई है। शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) ने 14 किलोमीटर लम्बी रिसाव वाली पुरानी पाईप लाईन को बदल पानी की बर्बादी को रोका है। इस वर्ष नए पानी के कनेक्शन पर रोक नहीं है तथा 1489 नए पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समयबद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष पुराने 154 कंट्रोल वाल्व्स बदले गए हैं।

उन्होंने कहा कि गुम्मा, गिरी तथा कोटी बराडी स्थित फिल्टरेशन प्रणालियों को स्तरोन्नत किया गया है जिसके कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति में तेजी सुनिश्चित हुई है। जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार करने के लिए की 20 स्थानों से जल के नमूने एकत्रित कर उनकी जांच आईजीएमसी में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिमला में पीलिया रोग का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सभी जल भण्डारण टैंकों की सुरक्षा एवं सफाई के लिए उनकी तालाबंदी तथा पार्श्वों और आमजनता की उपस्थिति में वर्ष में दो बार टैंकों की सफाई की जा रही है। एसजेपीएनएल द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप स्थापित 54 एमएलडी क्षमता के साथ अब 60 एमएलडी तक पानी उठाने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि क्लोरीन द्वारा पानी के शुद्धिकरण पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत तंत्र स्थापित किया गया है। सिवरेज संग्रहण एवं उपचार में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई

है जो अब 7 एमएलडी से बढ़कर 14 एमएलडी हो गया है।

एसजेपीएनएल ने दिसम्बर माह तक सभी घरों के रसोई एवं स्नानगृहों के जल को सिवरेज नेटवर्क के तहत लाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि एसजेपीएनएल ने वॉल्यूमेट्रिक बिलिंग आरम्भ की है जिसके फलस्वरूप घरेलू पानी के बिलों में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती हुई है। उपभोक्ता संबंधी जानकारी का डिजिटलीकरण किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को जून माह से पानी के बिलों की ऑनलाइन अदायगी की सुविधा प्राप्त होगी। बी.के. अग्रवाल ने कहा कि एसजेपीएनएल द्वारा आरम्भ किए गए आईईसी अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को पानी की बर्बादी रोकने एवं रिसाव संबंधी सूचना देने के लिए जागरूक किया गया है। एसजेपीएनएल नियमित रूप से पानी के संरक्षण के लिए कार्यालय परिसरों तथा होटलों में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि 'जल सखी' नामक महिला समूहों का गठन किया गया है जो पानी के रिसाव, ओवरफ्लो, दुरुपयोग तथा अन्य जल संबंधी शिकायतों की रिपोर्ट एसजेपीएनएल की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को देगा।

प्रधान सचिव शहरी विकास प्रबोध सक्सेना, आयुक्त नगर निगम पंकज राय, निदेशक (सिविल) हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड धर्म सिंह ठाकुर, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, निदेशक शिमला जल प्रबन्धन निगम, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और मुख्य अभियन्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

रोपवे प्रणाली के अध्ययन के लिए प्रतिनिधि मण्डल ने किया बोलोविया का दौरा

शिमला/शैल। आवासीय आयुक्त संजय कुंडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ला पाज़, बोलोविया का दौरा किया। प्रधान सचिव परिवहन जगदीश चंद्र शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक

यह प्रणाली विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित शहरों के लिए भूमिगत मेट्रो प्रणालियों की तुलना में अधिक अनुकूल और किफायती है।

प्रतिनिधि मंडल ने डोपेलमयर के



रोपवे कॉर्पोरेशन व डब्ल्यूपीसीओ के प्रबंधक प्रभाकर सत्ती भी उनके साथ थे। दौरे का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण परिवहन के समाधान के रूप में रोपवे प्रणाली का अध्ययन करना था।

भूमिगत मेट्रो, ट्राम, बीआरटी और मोनो रेल आदि सहित सभी विकल्पों की जांच के बाद प्रतिनिधि मंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि महानगरीय क्षेत्रों की शहरी गतिशीलता समस्याओं को हल करने के लिए रोपवे किफायती, जल्दी निष्पादन योग्य और पर्यावरण अनुकूल समाधान है।

दौरे के दौरान, प्रतिनिधि मंडल ने ला पाज़ रोपवे प्रणाली की तकनीक और संचालन का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि

कार्यालय का भी दौरा किया और इस परियोजना को निष्पादित करते समय उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विशेषज्ञों के साथ विस्तृत बातचीत की और अपने अनुभव को भी साझा किया।

चर्चा के दौरान, डोपेलमयर के विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्र की आवागमन समस्याओं का समाधान सुझाया। यदि इस रोपवे प्रणाली को राज्य में लागू किया गया तो यह न केवल शिमला, धर्मशाला और मनाली जैसे शहरों में होने वाली आवागमन समस्याओं को हल करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में अनुकूल और पर्यावरण मित्र कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिये जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी.....चाणक्य

सम्पादकीय

चुनाव आयोग की भूमिका पर उठते सवाल



निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यह जिम्मेदारी निभाने के लिये चुनावों की घोषणा के साथ ही पूरा प्रशासनिक तन्त्र आयोग के नियन्त्रण में आ जाता है यह व्यवस्था की गयी है। चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है और यह संहिता लागू होने के बाद सामान्य प्रशासनिक कार्यों को छोड़कर हर बड़े फैसले के लिये चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है। चुनावों के दौरान क्या-क्या आचार संहिता के दायरे में आता है और इस संहिता की उल्लंघना के लिये क्या-क्या प्रतिबन्धात्मक कदम आयोग उठा सकता है यह पूरी तरह परिभाषित हैं। चुनावों के दौरान आयोग की प्रशासनिक शक्तियाँ सर्वोच्च हो जाती हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उस पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। आयोग को सरकारी नियन्त्रण से बाहर इसलिये रखा गया है ताकि उसकी निष्पक्षता पर कोई आंच न आये।

लेकिन क्या इस बार चुनाव आयोग यह भूमिका निष्पक्षता से निभा पाया है। यह सवाल चुनावों के अन्तिम चरण तक आते-आते एक बड़ा सवाल बन कर देश के सामने खड़ा हो गया है। यह स्थिति बंगाल में हुई चुनावी हिंसा के बाद एक बड़ा मुद्दा बन गयी है। चुनाव आयोग के पास आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही आनी शुरू हो गयी थी। लेकिन आयोग ने इन शिकायतों की ओर तब तक उचित ध्यान नहीं दिया जब तक सर्वोच्च न्यायालय से एक तरह की प्रताड़ना उसे नहीं मिल गयी। इस प्रताड़ना के बाद आयोग ने कुछ नेताओं के चुनाव प्रचार पर कुछ समय के लिये प्रतिबन्ध लगाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमितशाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर आयी शिकायतों पर तब तक कुछ नहीं किया जब तक इस संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं नहीं आ गयी। यह याचिकाएं आने के बाद जब शीर्ष अदालत ने इस पर तीन दिन में फैसला लेने के निर्देश दिये तब इन लोगों को क्लीनचिट मिल गयी। इस क्लीनचिट को लेकर सवाल उठे हैं जिनका कोई जवाब नहीं आया है।

चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों से चुनाव करवा रहा है। ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर एक लम्बे समय से सवाल उठते आ रहे हैं। देश के कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में इस संदर्भ में याचिकाएं दायर हुई हैं। ईवीएम जब केरल विधानसभा के 1982 के चुनावों में एक विधानसभा हल्के में इस्तेमाल हुई थी तब इस पर उच्च न्यायालय में याचिका आ गयी थी। जब यह याचिका 1984 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची थी तब शीर्ष अदालत ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। उसके बाद 1998 में जब संसद में इस पर चर्चा हुई तब ईवीएम का चुनावों में उपयोग शुरू हुआ। लेकिन इसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठते रहे। जब भाजपा नेता डा. स्वामी ने इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की तब सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास ले लिये और वीवीपैट की इसमें व्यवस्था जोड़ दी जो अब पूरी तरह लागू हुई है। लेकिन वीवीपैट को पूरी तरह प्रमाणिक बनाने के लिये जब इक्कीस राजनीतिक दलों ने इसमें 50% मशीनों की परीचों की गणना की मांग की और सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग से इस बारे में जवाब मांगा तब आयोग ने यह कह दिया कि ऐसी गणना करने से चुनाव परिणाम में छः दिन की देरी हो सकती है। शीर्ष अदालत ने भी आयोग के जवाब को मानते हुए यह याचिका खारिज कर दी। क्या इससे जन विश्वास को धक्का नहीं लगा है? यदि चुनाव परिणामों की गणना में छः दिन का समय लगने से जन विश्वास जीता जा सकता था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? ईवीएम पर सन्देह करने का आधार तो चुनाव आयोग स्वयं दे रहा है। इससे जो स्थिति उभरती नजर आ रही है उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि ईवीएम फिर बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।

चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अन्त तक चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता का संकट गहराता चला गया है। जिस दंग से बनारस में तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द किया गया और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोई हस्ताक्षर नहीं किया उससे चुनाव आयोग के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा पर भी आंच आयी है। आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो प्रश्नचिन्ह बंगाल के संदर्भ में लगे हैं उनके परिणाम दूरगामी होंगे। क्योंकि बंगाल में हिंसा तो पहले चरण से ही शुरू हो गयी थी जो हर चरण में जारी रही। लेकिन आयोग ने जो कदम अमितशाह प्रकरण के बाद उठाया वह पहले क्यों नहीं उठाया गया। प्रशासन तो चुनाव आयोग के ही नियन्त्रण में था। यदि आज गृह सचिव और एडीजीपी को हटाया जा सकता है तो यही कदम पहले भी उठाया जा सकता था। अब अमितशाह प्रकरण के बाद चुनाव प्रचार पर दो दिन पहले ही रोक लगा देने से आयोग की निष्पक्षता पर और भी गंभीर आक्षेप आ गये हैं। और जब देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ही खत्म हो जायेगी तब पूरे चुनाव परिणामों पर भी अपने आप ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है। यह प्रश्नचिन्ह लगना सीधे सीधे अराजकता का खतरा इंगित करता है और यही सबसे घातक है। क्योंकि जब संस्थानों की विश्वसनीयता पर आंच आनी शुरू होती है तब उससे अराजकता ही पैदा होती है यह तय है।

खतरनाक है भारतीय सीमा पर आईएसआईएस की दस्तक



गौतम चौधरी

आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसने भारत में अपनी नई शाखा स्थापित की है। यह कितना सत्य है यह तो पड़ताल का विषय है लेकिन अगर इसमें रतीभर भी सत्यता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। दरअसल, इस बात की घोषणा संगठन ने 10 मई को की। आपको बता दें कि आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़पों के बाद इस तरह की घोषणा की गई है। इस्लामिक स्टेट के मुखपत्र “अमाक” के मुताबिक भारत में खोली गई नई शाखा का अरबी नाम “विलायाह ऑफ हिंद” है।

हालांकि जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस दावे को खारिज कर दिया है लेकिन इन दिनों जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उससे साफ लगने लगा है कि आतंकवादी पहले से ज्यादा पेशेवर तरीके से हमले कर रहे हैं। इस मामले में इस्लामिक चरमपंथियों पर नजर रखने वाले एसआईटीई इंटेल ग्रुप की निदेशक रीता काटज का मानना है कि इस्लामिक स्टेट ने अमशिपुरा में भारतीय बलों के साथ झड़पों का दावा करते हुए अपना नया हिंद प्रांत घोषित किया है। इस्लामिक स्टेट ने हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि भारत के किस इलाके में ये शाखा खोली गई है लेकिन स्वाभाविक रूप से यह शाखा उनकी वहीं खुली होगी जहां ज्यादा संख्या में मुसलमान रहते हैं। आपको बता दें कि केरल पहले से आईएस की जड़ में है। यहां के कई युवा आई एस के चंगुल में फंच चुके हैं। यहां की कई युवतियां भी सीरिया आदि देशों में आतंकी संगठन आईएस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है।

जानकारों की मानें तो पश्चिम एशिया में आईएस की जमीन खिसकने के बाद अब यह दूसरे इलाके की ओर अपना रुख कर रहा है। उसके टारगेट में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया है। अभी हाल ही में ईरान में आतंकी हमले हुए, इसके बाद पाकिस्तान में हमले हुए, फिर इंडोनेशिया और मलेशिया में हमले

हुए और इसके बाद श्रीलंका में। जानकार बताते हैं कि ये सारे हमले आईएस के द्वारा किए जा रहे हमलों की शैली के हमले हैं। ये तमाम हमले फिदायीन थे और बेहद पेशेवर तरीके से इसको अंजाम दिया गया। इससे इस आशंका को बल मिलने लगा है कि आईएस अब दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को अपना पनाहगाह बना रहा है। यदि ऐसा है तो भारत को सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि भारत के युवा अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में मध्य-पूर्व के देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। वे वहां आईएस के नुमाइंदों के साथ संपर्क में होंगे इसकी जानकारी भारतीय एजेंसियों को नहीं हो सकती है। वे कब आतंकवादी बन जाते हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त करना कठिन है क्योंकि आतंकवाद का यह मॉड्यूल बेहद खतरनाक है। वे किसी भी समय भारत में मोर्चा खोल सकते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम वाहुल्य देश है। इसलिए हमारी सरकार, समाज और अमन पसंद नागरिकों को सतर्क रहना होगा।

इस्लामिक स्टेट प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी ऑटोमन की तरह दुनिया के मुसलमानों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते हैं। हालांकि उससे इस्लामी देशों की स्वतंत्रता भी खंडित होगी लेकिन इस्लामिक देशों में बड़े पैमाने पर बगदादी के समर्थक हैं। मुस्लिम युवक एवं युवतियों के बीच बगदादी के फौलोवर बड़ी संख्या में हैं। बगदादी के चिंतन को भारत जैसे देशों में बड़े पैमाने पर प्रचार करने वाले मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाईक जैसे एक पक्षीय चिंतक अपनी चरमपंथी सोच के कारण जाने-अजाने में आईएसआईएस को सहयोग कर देते हैं। बगदादी के समर्थक भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान में फैले हैं। श्रीलंकाई आतंकी हमले के बाद यह साबित हो गया है कि बगदादी समर्थक अनवरत रूप से अपने काम में लगे हैं। इधर आईएसआईएस को लग रहा है कि अगर वे मध्य-पूर्व में असफल हुए तो दक्षिण एशिया उनके लिए बेहद अनुकूल हो सकता है। इसलिए वे लगातार भारतीय उप महाद्वीप को टारगेट कर रहे हैं। इन दिनों भारत में भी एक खास प्रकार की हवा चल रही है। मुस्लिम जमात में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि भारत के बहुसंख्यक हिन्दू उनके धार्मिक

पहचान को खत्म करना चाहते हैं। यही नहीं प्रचार तो यहां तक किया जा रहा है कि सत्ता में बैठे लोग भी बहुसंख्यकों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। जहां-तहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देश के अंदर एक खास लॉबी के द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों पर भी आक्रमण हो रहा है। इस प्रकार देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच गहरी खाई खोदने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आईएसआईएस को स्वतः मौका मिल जाएगा। पहले इस्लामिक आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से सहयोग मिलता था लेकिन अब चरमपंथियों से खुद पाकिस्तान भी परेशान हो रहा है। जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं, भारतीय चरमपंथियों को अगर आईएसआईएस से सहयोग मिलने लगा है तो अब इस मामले में पाकिस्तान की भूमिका सीमित रह जाएगी और तब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध भारत के लिए और कठिन हो जाएगा।

सच पूछिए तो दुनिया में जिस प्रकार अन्य धर्म अमन पसंद है, उसी प्रकार इस्लाम भी अमन का संदेश देता है। इस्लाम को गलत तरीके से प्रचारित किया जाता रहा है। इसमें पश्चिमी मीडिया की बड़ी भूमिका है। आईएसआईएस या फिर अलबगदादी के बारे में बताया जाता है कि वह पहले अमेरिका का समर्थक था और बाद में उसने अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। जिस प्रकार ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला ठीक उसी प्रकार अलबगदादी भी अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है लेकिन अलबगदादी का विरोध कर या इस्लाम का विरोध कर आईएसआईएस को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भारत को सॉफ्ट रणनीति पर काम करना होगा। इस प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के पास खुद का इजाद किया हुआ बड़ा हथियार, सूफीवाद है। सूफीवाद और इस्लामी रहस्यवाद के हथियार से इस राक्षक का संहार किया जा सकता है। साथ ही भारतीय राजनेताओं को, रणनीतिकारों को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय कानून और संविधान पर देश के अल्पसंख्यकों का विश्वास बना रहना चाहिए। अगर वह खंडित हुआ तो भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी।

साइबर क्राइम्स कैसे करें खुद का बचाव?

— श्रीप्रकाश शर्मा —

भी क्लियर कर दें ।

पासवर्ड काफी स्ट्रॉंग रखें

सच पूछें तो अपने ईमेल आइडी को सिक्क्योर और सेफ रखने के लिए एक स्ट्रॉंग पासवर्ड सबसे बड़ी और पहली शर्त है। स्ट्रॉंग पासवर्ड बनाने के लिए आपको कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए । सबसे पहली बात तो यह है कि यह कम से कम आठ डिजिट या लेटर्स से कम का नहीं होना चाहिए। अपने पासवर्ड में अल्फाबेट लेटर्स के साथ नुमेरल्स और सिम्बल्स का भी यूज करना चाहिए।

.....देशबन्धु से साभार

साइबर का अर्थ कंप्यूटर होता है और यही कारण है कि साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किये जानेवाले सभी प्रकार के गैर-कानूनी और धोखाधड़ी की एक्टिविटीज साइबर क्राइम की श्रेणी में शामिल किये जाते हैं। सूचना तकनीक के रूप में कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के फलस्वरूप साइबर क्राइम का दायरा भी बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है।

किसी यूजर के कंप्यूटर से इंटरनेट की मदद से उनके पर्सनल डाटा की चोरी से लेकर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के कॉपीराइट का गैरकानूनी प्रयोग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बुल्लियंग (डराना और ब्लैकमेलिंग), वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर कई अन्य अपराध भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त स्पैम मेल के द्वारा अपने वस्तु और सेवा का प्रमोशन करना, फिशिंग के माध्यम से किसी यूजर के प्राइवेट डाटा में संध लगा कर बैंकों से धन की निकासी करना, ड्रग ट्रेफिकिंग करने के अतिरिक्त कई अन्य गैरकानूनी कार्य भी साइबर अपराध की कटेगरी में सम्मिलित की जाती हैं ।

आज हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम इंटरनेट और कंप्यूटर के बिना अपना काम बिलकुल नहीं चला सकते हैं । लिहाजा यह अनिवार्य है कि जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज कर रहे हों तो हमें कुछ ऐसी सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे हम साइबर क्राइम की घटनाओं से खुद की रक्षा कर पायें।

अपने कंप्यूटर के लिए एक स्ट्रॉंग पासवर्ड सबसे अनिवार्य

वैसे तो यह सामान्य-सी बात है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चला रहे हों तो आप अपने पीसी को एक स्ट्रॉंग पासवर्ड से सिक्क्योर कर लें । जब पीसी पासवर्ड से सुरक्षित हो जाता है तो इसका इस्तेमाल कोई अन्य व्यक्ति गलत कार्य के लिए नहीं कर सकता है और न ही कोई अन्य व्यक्ति आपके कंप्यूटर से कोई प्राइवेट इनफार्मेशन चुरा सकता है ।

किन्तु जब भी आप अपने कंप्यूटर को किसी पासवर्ड से सिक्क्योर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पासवर्ड हमेशा ही स्ट्रॉंग होना चाहिए । पासवर्ड का क्रिएशन लेटर्स, सिम्बल्स और नुमेरल्स का मिक्सचर हो तो यह बहुत इफेक्टिव माना जाता है । इसके साथ-साथ आप पासवर्ड के लिए लोअर केस लेटर्स और अप्पर केस लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं।

यदि आप एक से अधिक एकाउंट्स का यूज कर रहे होते हैं तो आपको उन सब एकाउंट्स के लिए एक कॉमन पासवर्ड का यूज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम का खतरा बढ़ जाता है । आप अपने मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, बर्थडे जैसे नंबरों का भी यूज अपने पासवर्ड के लिए नहीं करें क्योंकि इस प्रकार के पासवर्ड को गेस करना कठिन कार्य नहीं होता है।

सोशल मीडिया के यूज के बारे में आपकी सतर्कता जरूरी

सोशल मीडिया के रूप में फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग इत्यादि के यूज के बारे में हमें सावधान रहने की जरूरत है । सोशल मीडिया के इन साइट्स पर कुछ भी अपलोड करने पर वे सभी दुनिया भर के यूजर्स के लिए हमेशा के लिए पोस्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करें जो हमारे लिए बेहद प्राइवेट और सेंसिटिव इनफार्मेशन वाला हो और जिनके लीक हो जाने पर हमें किसी खतरे का सामना करना पड़े।

सेंसिटिव और पर्सनल

इनफार्मेशन का प्रोटेक्शन जरूरी

कई बार हमें ऑनलाइन शॉपिंग के अतिरिक्त इंटरनेट बैंकिंग के यूज के लिए कई पर्सनल इनफार्मेशन शेयर करनी होती है । खासकर यूजर के एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर, बैंक्स अकाउंट नंबर इत्यादि की प्राइवैसी के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपके ईमेल इनबॉक्स में ऐसे मेल्स आते हैं जिसकी स्पेलिंग और ग्रामर शुद्ध नहीं है तो यह मान लेनी चाहिए कि ऐसे ईमेल फेक हैं और इसीलिए इन सभी मेल्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बेहतर हो कि इस प्रकार के मेल्स को कभी भी ओपन नहीं करें।

ईमेल आइडी को भी हैक होने से बचाएं

फास्ट तकनीक और इंटरनेट के तेजी से बढ़ते प्रयोग के वर्तमान युग में ईमेल आइडी का प्रचलन अब एक सामान्य-सी बात हो गयी है । लेकिन यूजर के द्वारा अपने ईमेल आइडी को सिक्क्योर और सेफ रखने के बारे में लापरवाही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ईमेल आइडी केवल कम्युनिकेशन और कॉन्सपेंडेंस के एक मॉडर्न मीडियम के रूप में ही कार्य नहीं करता है बल्कि यह कई सेंसिटिव डाटा और प्राइवेट इनफार्मेशन को भी सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में ईमेल के हैक हो जाने पर यूजर के डाटा और इम्पोर्टेंट इनफार्मेशन की प्राइवैसी और सिक्क्यूरिटी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए अपने ईमेल आइडी को हैक होने से बचाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉंग पासवर्ड की बड़ी आवश्यकता होती है। आइये देखें कि अपने ईमेल आइडी को सिक्क्योर और सेफ रखने के लिए और इसे किसी हैकर से बचाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं-

रिकवरी डिटेल

जिस ईमेल आइडी का आप यूज कर रहे हैं उसे अपने मोबाइल नंबर और अन्य ईमेल आइडी के द्वारा सपोर्ट कर देने से ईमेल आइडी को रिकवर करने में काफी मदद मिलती है। सिक्क्यूरिटी के लिए कुछ ऐसे प्रश्न भी सेट करना चाहिए जिनके आंसर आसानी से कोई हैकर अनुमान नहीं लगा पाए।

रेगुलर यूज करते रहें अपने ईमेल आइडी को

कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई यूजर अपने ईमेल आइडी को रेगुलरली यूज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ईमेल आइडी के हैक हो जाने पर यूजर को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है और यूजर की डाटा की प्राइवैसी और सिक्क्यूरिटी खतरे में पड़ जाती है । इसीलिए यह जरूरी है कि अपने ईमेल आइडी को नियमित रूप से लॉग-इन करते रहें ।

पब्लिक वाई-फाई के यूज से सावधान रहें

अपने ईमेल आइडी को लॉग-इन करने के लिए पब्लिक वाई-फाई का यूज करना भी खतरे से खाली नहीं है । क्योंकि ये प्री या पब्लिक वाई-फाई ट्रिक्स से भरे होते हैं । पब्लिक वाई-फाई के यूज से कोई भी हैकर यूजर के ईमेल आइडी के कई इम्पोर्टेंट इनफार्मेशन में संध मार सकता है और उसे हैक कर सकता है। लिहाजा पब्लिक वाई-फाई को यूज करने से बचने की जरूरत है।

मल्टीपल सिक्क्यूरिटी का यूज करें

मल्टीपल सिक्क्यूरिटी का अर्थ यह है कि अपने ईमेल आइडी को डबल ऑथेंटिकेशन से सिक्क्योर करें। प्रायः सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां मल्टीपल सिक्क्यूरिटी का ऑप्शन अवेलेबल कराती हैं। इसके अंतर्गत सिक्क्यूरिटी सेटिंग्स में मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना होता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक लॉग-इन पर यूजर के मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है जिसको

फीड करने के बाद ही ईमेल आइडी लॉग-इन हो पाता है।

अपरिचित ईमेल और अटैचमेंट को ओपन नहीं करें

प्रायः हर एक ईमेल आइडी यूजर के ईमेल इनबॉक्स में कई ईमेल्स आते हैं जिनके बारे में यूजर को कोई जानकारी नहीं होती है और जो यूजर से बिलकुल रिलेटेड नहीं होती हैं। इस प्रकार के ईमेल अटैचमेंट या इनबॉक्स को बिलकुल ओपन नहीं करें क्योंकि ऐसा करने पर आपके कंप्यूटर में कुछ मैलवेयर इंस्टाल हो सकते हैं जो हैकर को आपके ईमेल

आइडी के बारे में सीक्रेट इनफार्मेशन सेंड कर सकता है और आपका ईमेल आइडी हैक हो सकता है ।

लॉगआउट करना न भूलें

जब भी आप अपने ईमेल आइडी को लॉग-इन करें तो इसे लॉग-आउट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर जब कोई दूसरा यूजर आपके कंप्यूटर को यूज करेगा तो आपका ईमेल आइडी बिना पासवर्ड के ओपन हो जायेगा और आपकी महत्वपूर्ण इनफार्मेशन हैक कर लिए जायेगी। इसके अतिरिक्त ईमेल के लॉगआउट करने के बाद इसकी हिस्ट्री

प.बंगाल में राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता या दुश्मनी

— डॉ. नीलम महेंद्र —

हिंसा के लिए भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को यह बोलने से पहले इस बात को समझना चाहिए कि अगर वे सही कह रही हैं और यह हिंसा भाजपा की रणनीति का हिस्सा थी तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनकी प्रशासनिक विफलता है। लेकिन अगर यह हिंसा तृणमूल की साज़िश थी तो यह उनकी राजनैतिक पराजय की स्वीकारोक्ति है।

क्या ममता हार मान चुकी है?

आज़ाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार चुनावी हिंसा के कारण देश के एक राज्य में चुनाव प्रचार को 20 घंटे पहले ही समाप्त करने का आदेश चुनाव आयोग ने लिया है। बंगाल में चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ही शायद चुनाव आयोग ने बंगाल में सात चरणों में चुनाव करवाने का निर्णय लिया था लेकिन यह वाकई में खेद का विषय है कि अब तक जो छः चरणों में चुनाव हुए हैं उनमें से एक भी बिना रक्तपात के नहीं हो पाया। यह चुनावी हिंसा बंगाल में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की स्थिति बताने के लिए काफी है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि ममता अपने राज्य में होने वाले उपद्रव के लिए अपने प्रशासन को नहीं मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वैसे तो ममता बनर्जी ने अपने इरादे इसी साल के आरंभ में ही जता दिए थे जब उन्होंने मोदी के विरोध में कलकत्ता में 22 विपक्षी दलों की एक रैली आयोजित की थी। इस रैली में उन्होंने मंच से ही कहा था कि बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर बंगाल में उतरने ही नहीं देंगी और देश ने देखा, जो उन्होंने कहा वो किया। इससे पहले भी देश में लोकतंत्र की चिंता करने वाली इस नेत्री ने 2018 में बीजेपी को रथयात्रा की अनुमति नहीं दी थी। आश्चर्य इस बात का भी होना चाहिए कि बंगाल में ममता की रैलियां तो बिना किसी उत्पात के हो जाती हैं लेकिन भाजपा की रैलियों में हिंसा हो जाती है। यह अत्यंत दुःखद है कि जिस वामपंथी शासन काल में होने वाली हिंसा और अराजकता से मुक्ति दिलाने के नाम पर ममता ने बंगाल की जनता से वोट मांगे थे आज सत्ता में आते ही वो खुद भी उसी राह पर चल पड़ी हैं। अभी पिछले साल ही बंगाल में हुए पंचायत चुनाव बंगाल की राजनीति की दिशा और वहाँ पर लोकतंत्र की दशा बताने के लिए काफी थे। वो प्रदेश जिसकी मुख्यमंत्री ने इसी साल जनवरी में ‘‘लोकतंत्र और संविधान की रक्षा’’ के लिए सम्पूर्ण विपक्ष के साथ मिलकर रैली की थी उसी प्रदेश में उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मात्र सात माह पहले हुए पंचायत जैसे चुनाव भी बिना हिंसा के संपन्न नहीं होते। आप इसे क्या कहिएगा कि इन पंचायत चुनावों की 58692 सीटों में से 20159 सीटें तृणमूल कांग्रेस द्वारा बिना चुनाव के ही जीत ली जाती हैं। जी हाँ, इन सीटों पर एक भी वोट नहीं पड़ता है और तृणमूल के उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते हैं। क्योंकि इन सीटों पर लोगों को

नामांकन दाखिल ही नहीं करने दिया जाता। और अब लोकसभा चुनावों के दौरान हिंसा का जो तांडव बंगाल में देखने को मिल रहा है वो देश के किसी राज्य में नहीं मिल रहा यहाँ तक कि बिहार और जम्मू कश्मीर तक में नहीं। वो भी तब जब राज्य में केन्द्रीय बलों की 713 कंपनियाँ और कुल 71 हजार सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हों। सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में इतने सुरक्षा बल के होते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में उस स्तर की हिंसा होती है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी जाती है और अमित शाह को कहना पड़ता है कि अगर सीआरपीएफ की सुरक्षा न होती तो मेरा बंगाल से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। ऐसे राज्य में एक आम आदमी की क्या दशा होती होगी? इस हिंसा के लिए भाजपा ने सीधे सीधे ममता को दोषी ठहरा कर चुनाव आयोग से शिकायत की जबकि ममता का कहना है कि इस हिंसा के लिए भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को यह बोलने से पहले इस बात को समझना चाहिए कि अगर वे सही कह रही हैं और यह हिंसा भाजपा की रणनीति का हिस्सा थी तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनकी प्रशासनिक विफलता है। लेकिन अगर यह हिंसा तृणमूल की साज़िश थी तो यह उनकी राजनैतिक पराजय की स्वीकारोक्ति है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि जब अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को काबू में रखने में जब वे विफल होती हैं और ऐसे में जब चुनाव आयोग को दखल देना पड़ता है तो उन्हें चुनाव आयोग में आर एस एस के लोग नज़र आते हैं। जब राज्य में हिंसा को रोकने में नाकाम रहने के कारण चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार पर समय से पहले रोक लगाने का फैसला सुनाना पड़ता है तो ममता प्रेस कॉन्फेंस करके चुनाव आयोग पर भाजपा का एजेंडा चलाने जैसे आरोपों की बौछार लगा देती हैं। जबकि वे जानती हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो इससे पहले योगी आदित्यनाथ मेनका गांधी साधवी प्रज्ञा सिद्धू आजूम खान अनेक नेताओं पर भी फैसला दे चुकी है और इन सभी ने चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान किया किसी ने आरोप नहीं लगाए लेकिन दीदी को गुस्सा ज़रा ज्यादा आता है। सहिष्णुता की बात करने वाली

दीदी को समझना चाहिए कि उनकी सहनशीलता देश देख रहा है। इससे पहले भी जब शारदा चिटफंड घोटाले की जाँच करने के लिए सीबीआई के अफसर बंगाल आए थे तो ममता के रवैये से राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इतना ही नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाली दीदी का एक मीम बनाने पर एक महिला को जेल में डाल देती हैं। और तो और कोर्ट के उस महिला को तत्काल रिहा करने के आदेश के बावजूद उस महिला को 18 घंटे से अधिक समय तक जेल में ही रखा जाता है और रिहा करने से पहले उनसे एक माफीनामा भी लिखवाया जाता है। दीदी को यह समझना चाहिए कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मीडिया को मैनेज किया जा सकता है सोशल मीडिया को नहीं। उन्हें समझना चाहिए कि देश की जनता पर ‘‘वो क्या कहती है उससे अधिक प्रभाव वो क्या करती हैं’’ का पड़ता है। एक तरफ वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करती हैं तो दूसरी तरफ वो उसी संविधान का तिरस्कार करती हैं जब वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर देती हैं। वो उन्हें जेल भेजने की बात करती हैं। इतना ही नहीं वो एक मिनट में बीजेपी के दफ्तर पर कब्ज़ा कर लेने की बात करती हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वो विपक्षी गठबंधन की स्थिति में खुद को देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखती हैं तो क्या उनके इस आचरण से देश भी उनमें अपने लिए एक प्रधानमंत्री देख पाएगा? दरअसल दीदी की राजनैतिक महत्वाकांक्षा ने बीजेपी से उनकी राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता को कब राजनैतिक दुश्मनी का रूप दे दिया शायद वे भी नहीं समझ पाईं। लेकिन बंगाल में ताज़ा हिंसा के दौर ने जिसमें अनेक राजनैतिक हत्याएं तक शामिल हैं, सभी सीमाओं को लांघ दिया है। यह चुनाव अब ममता बनाम मोदी की सीमा से बाहर आ चुका है। बंगाल में यह लड़ाई केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के दायरे से भी बाहर आ गई है। अब यह लड़ाई है देश के एक राज्य के लोगों के अधिकारों की, कि क्या वो राज्य देश के संविधान और कानून से चलेगा या तानाशाही पूर्ण रवैये से।

मुख्य सचिव ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति पर की बैठक चौथी विश्व एगोफोरेस्ट्री काँग्रेस में पोस्टर प्रेजेंटेशन करेंगे नौणी के छात्र

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने नई दिल्ली में भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग, और इसके कारण राज्य सरकार जनता, जनता के प्रतिनिधियों और मीडिया के सामने नाराजगी की स्थिति का सामना



जहाजरानी मंत्रालय के सचिव संजीव रंजन के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) की सभी मार्गों की दयनीय स्थिति के बारे में बैठक की।

उन्होंने कहा कि एनएचआई अच्छी तरह से और नियमित रूप से 774 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में नियमित रखरखाव के लिए आवश्यक फोल्ड स्टाफ व श्रमिका की कमी के कारण यातायात के लिए सुरक्षित नहीं हैं

कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि इनकी रखरखाव गतिविधियों को राज्य लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग को एनएचआई के जमा कार्यों डिपॉजिट वर्क्स के रूप में सौंपा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्टेट पीडब्ल्यूडी के पास नियमित रखरखाव के लिए पर्याप्त फिल्ट्र जनशक्ति और बुनियादी ढांचा है।

बी.के. अग्रवाल ने संजीव रंजन को किरतपुर-नेरचौक परियोजनाओं (84.38 किलोमीटर) के फोर-लेनिंग

का कार्य जोकि जून, 2018 से बन्द पड़ा है, के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग कुल्लू व मण्डी जैसे पर्यटन स्थलों तक जाने वाली जीवनरेखा है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस परियोजना में दोबारा कार्य शुरू करने व 2012 से लम्बित कार्य को बिना किसी विलम्ब से पूरा करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि नेरचौक-पंडोह परियोजना (26.29 किलोमीटर) का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और उन्होंने एनएचआई से इस परियोजना पर कार्य को तेज करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने पिजौर-बढ़ी-नालागढ़ फोर-लेनिंग परियोजना के लिए 31.400 किलोमीटर की लम्बाई (हिमाचल प्रदेश में 17.00 किलोमीटर) में हो रहे विलम्ब के बारे में भी अवगत करवाया और कहा कि इन सड़कों का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी मंत्रालय के सचिव संजीव रंजन ने आश्वासन दिया कि इन सड़कों को प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा और यह भी आश्वासन दिया कि इन सड़कों पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा।

शिमला/शैल। डॉ. वाईएस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के डॉक्टर छात्र कृष्ण लाल गौतम को 20 से 22 मई, 2019 के बीच फ्रांस के मोंटपेलियर में आयोजित होने वाली चौथी विश्व एगोफोरेस्ट्री काँग्रेस में पोस्टर प्रेजेंटेशन करने के लिए चुना गया है।

इस काँग्रेस के लिए प्रस्तुत सार के आधार पर विश्व एगोफोरेस्ट्री काँग्रेस

हैं। उनकी पोस्टर प्रस्तुति का शीर्षक-मोरस आधारित एगोफोरेस्ट्री सिस्टम के तहत लेपिडियम सैटिवम के उत्पादन पर विभिन्न प्रकार की जैविक खाद का प्रभाव है।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एचसी शर्मा ने कहा कि एक छात्र के लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजन के लिए चुना जाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कृष्ण लाल न केवल



संस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे बल्कि इस कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।

चौथी विश्व एगोफोरेस्ट्री काँग्रेस में दुनिया भर के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों और प्रमुख मुख्य वक्ता महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करेंगे। यह विकासशील और

विकसित देशों से तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करेगा और व्यापक सामाजिक भागीदारी के साथ एक सहयोगी प्रयास का समर्थन करेगा। इस काँग्रेस का समग्र उद्देश्य कृषि-नीति विज्ञान की प्रगति में योगदान देना है और विज्ञान-नीति की दूरी को कम करना है। इस आयोजन के दौरान एगोफोरेस्ट्री और जलवायु परिवर्तन, एगोफोरेस्ट्री, खाद्य सुरक्षा और पोषण, एगोफोरेस्ट्री का अभिग्रहण, एगोफोरेस्ट्री नीतियां आदि विषयों पर चर्चा होगी।

की वैज्ञानिक समिति द्वारा कृष्ण लाल को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 1,921 यूरो की राशि भी दी जाएगी। इसमें पंजीकरण और अन्य शुल्क के लिए 340 यूरो शामिल हैं जबकि यात्रा, आवास, वीजा आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए 1,481 यूरो का भुगतान किया जा रहा है। कृष्ण लाल ने नौणी विवि से अपनी बीएससी वानिकी और एमएससी एगोफोरेस्ट्री की डिग्री पूरी की है। वह वर्तमान में यूनिवर्सिटी से एगोफोरेस्ट्री में अपने पीएचडी की पढ़ाई कर रहे

सरकार लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत: पूर्णिमा चौहान

शिमला/शैल। सचिव में मदद करेगा। प्रशासनिक सुधार (एआर) डॉ. पूर्णिमा चौहान ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 पर एक कार्यशाला



की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के भरसक प्रयास कर रही है ताकि सार्वजनिक सेवाएं प्रदेश के लोगों के लिए सही मायनों में वास्तविकता बन सकें।

उन्होंने कहा कि नागरिकों के जागरूक न होने पर भी प्रदेश सरकार समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार 27 विभागों की 188 समयबद्ध सेवाएं प्रदान कर रही है और इन सेवाओं का अनुश्रवण राज्य तथा जिला स्तर पर 13000 नोडल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यापक कार्य है तथा अधिकारियों और नागरिकों के लिए इसका पूरा खाका तैयार किया गया है जोकि नागरिकों के विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने

उन्होंने कहा कि 9 वेब पोर्टलों के माध्यम से लगभग 73 प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही

हैं ताकि दूरदराज के लोगों को सरकारी सुविधाओं तथा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य या जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान घरद्वार पर सम्भव हो सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बिना किसी विलम्ब से शीघ्रता से सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्णता के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड भी आरम्भ किया जा रहा है। इसकी मदद से मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की जानकारी की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों के विभिन्न आंकड़े व गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा जिससे सभी विभागों की चौबीस घण्टे सूचना मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 2018 में 12 छोटे राज्यों में पहले

स्थान पर आंका गया है। प्रदेश सात विषयों, अठारह फोकस विषयों तथा एक सौ मानकों के एक स्व: मूल्यांकन तंत्र के रूप में शासन प्रदर्शन को मापने के लिए जिला सुशासन सूचकांक में पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि हमने जिला स्तर पर भी अनुक्रमणिका तैयार की है और समग्र प्रदर्शन में शिमला को सभी जिलों में प्रथम श्रेणी में रखा गया है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम हिमाचल प्रदेश के लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। अधिनियम में सेवाएं प्रदान न करना अथवा पर्याप्त एवं उचित कारणों के बिना सेवाएं प्रदान करने में विलंब की स्थिति में जिम्मेवार अधिकारी को पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें सार संग्रह पर पहले ही छः मामले प्राप्त हो चुके हैं और इन पर जुर्माना लगाया जा चुका है। इससे न केवल सुशासन के मानकों में सुधार होगा, बल्कि समाज को सुशासन के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान होगा।

संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनिल सेमवाल, उप सचिव (राजस्व) पी.के. टॉक, उप निदेशक (उद्योग) संजय शर्मा, सचिव, हि.प्र. राज्य सूचना आयोग कृष्ण कुमार तथा उप मुख्य अभियंता (एचपीएसईबीएल) विद्युत एन.पी. गुप्ता ने कार्यशाला में पावर प्वाइंट पर प्रस्तुतियां दीं।

कार्यशाला के दौरान उप सचिव राजेश शर्मा, प्रो. आर.एस. कपूर, हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान, प्रशासनिक सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में उपस्थित थे।

डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। डॉ. वाईएस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी नौणी में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित



किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संघठन द्वारा किया गया जिसका समन्वय व्यापार प्रबंधन विभाग ने किया। इसमें एमएससी और एमबीए के 120 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न पेशेवरों और समूहों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिभागियों को तैयार करने के साथ-साथ उनके संचार और पारस्परिक कौशल को बढ़ाना था।

चंडीगढ़ की द ट्रांसफार्मर्स-वैल्यू क्रिएटर्स कंपनी की लाइफ स्किल कोच, मंजूला सुल्लरिया ने इस कार्यक्रम में छात्रों को प्रशिक्षण दिया। अलग-अलग सत्रों में आत्मविश्वास निर्माण, व्यक्तित्व, तनाव प्रबंधन, रोजगार क्षमता, संचार, टीम निर्माण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों से ज्ञान साझा किया

गया। कार्यक्रम का उद्घाटन छात्र कल्याण अधिकारी डॉ. कुलवंत राय शर्मा ने किया। उन्होंने सफल कैरियर में अच्छे

व्यक्तित्व और संचार कौशल की भूमिका की बात कही। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वह इस कार्यक्रम में पूरे मन से भाग लें क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कौशल सीखने के साथ साथ उन्हें अपने सहपाठियों को भी ठीक से समझने का मौका मिलेगा।

कार्यक्रम समन्वयक डा. के.के. रैना ने इस अवसर पर छात्रों से प्रशिक्षण में सीखे गए गुर को अपने आत्मविश्वास, धैर्य, संचार और सामाजिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान सीखा गया कौशल, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मददगार होगा। छात्र कल्याण संघठन के डॉ. विनीत शर्मा और व्यापार प्रबंधन विभाग के संकाय भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

परमाणु बिजली ग्रीनहाऊस गैसों के लोकापाल की वेबसाइट का उद्घाटन उत्सर्जन में कमी ला सकती है:उपराष्ट्रपति

शिमला/शैल। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि परमाणु बिजली ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में व्यापक कमी ला सकती है और उसमें देश में बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा



करने का सामर्थ्य मौजूद है। नायडू ने परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन विश्व की मौजूदा दौर की सबसे प्रमुख परमाणु चिंताओं में से एक है।

उन्होंने कहा कि आज यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आधुनिक प्रौद्योगिकियां सुरक्षित और विश्वसनीय हों। उपराष्ट्रपति ने कहा कि परमाणु बिजली ऊर्जा के विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्पों में से एक है और

उन्होंने 40 वर्षों से ज्यादा असें से बिना किसी गंभीर घटना के परमाणु बेड़े का संचालन करने के रिकॉर्ड के लिए इसकी सराहना की।

नायडू ने कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा में भारत की बढ़ती दिलचस्पी का आधार यह गहन विश्वास है कि अणु की शक्ति का इस्तेमाल देश के मानवीय और सामाजिक विकास को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत सोच-समझकर आगामी वर्षों के लिए अल्प-कार्बन विकास वाले म डल का अनुसरण करने का महत्वपूर्ण विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण में कमी लाना एक बड़ी चुनौती है। विविध महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करने

के लिए अन्वेषण की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को ग्रहण करने के एएमडी के प्रयासों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि देश में तीन लाख टन से ज्यादा यूरैनियम ऑक्साइड के भंडार मौजूद हैं और लगभग 1200 मिलियन टन बीच सैन्ड मिनिरल के भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरैनियम संसाधन में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास एएमडी द्वारा किया गया है। शुरूआती 60 साल के कार्यकालों के दौरान मिले लगभग एक लाख टन से लेकर उसके

बाद के 10 वर्षों में लगभग 2 लाख टन अतिरिक्त भंडार की खोज किया जाना बेहद सराहनीय है।'

नायडू ने विश्वास व्यक्त किया कि कुडप्पा बेसिन सहित देश के विभिन्न भागों में एएमडी के अन्वेषण से और ज्यादा यूरैनियम की खानों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त होगा।

यूरैनियम, दुर्लभ धातुओं और आर्सेनिक भंडारों वाले देश भर के अनेक अनुकूल भौगोलिक क्षेत्रों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे परमाणु बिजली कार्यक्रम की निरंतर वृद्धि के लिए परमाणु खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भरता हासिल करना संभव हो सकेगा। देश में बिजली की बढ़ती मांग पर विचार करते हुए भविष्य में परमाणु ऊर्जा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उन्होंने कहा, 'अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए हमें नवीन और ज्यादा दक्ष प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी।'

इस अवसर पर एएमडी के निदेशक एम.बी. वर्मा और अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी उपस्थित थे।

इससे पहले एएमडी के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति के समक्ष अपने संगठन के कार्यकलापों के बारे में प्रस्तुति पेश की। उपराष्ट्रपति ने एएमडी के 70 वर्षों के अन्वेषण और अनुसंधान के सम्मान में 'कुडप्पाएकाश्रमक' पटिका का भी अनावरण किया।

किलोग्राम, केल्विन, मोल और एंपियर जैसी मापक इकाइयों की दुनिया को मिली नई परिभाषा

शिमला/शैल। दशकों तक प्रयोगशालाओं में किए गए गहन वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद आखिर दुनिया के वैज्ञानिकों ने 16 नवंबर 2018 को बीआईपीएम में माप-तौल पर आयोजित सम्मेलन में माप तौल की सात अंतरराष्ट्रीय इकाइयों में से चार, किलोग्राम (भार मापक इकाई), केल्विन (ताप मापक इकाई), मोल (पदार्थ मापक इकाई) और एंपियर (विद्युत मापक इकाई) को विश्व स्तर पर फिर से परिभाषित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था।

यह परिभाषा पूरी दुनिया में आज विश्व माप विज्ञान दिवस के दिन से लागू हो रही है। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1875 को आज ही के दिन दुनिया के 17 देशों के प्रतिनिधियों ने माप तौल की एक सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली तय करने के लिए मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इस सम्मेलन ने वैश्विक सहयोग के माध्यम से नाप तौल विज्ञान और उसकी औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामाजिक उपयोगिता की रूपरेखा तय करने का मार्ग प्रशस्त किया था।

हालांकि आज के दिन से लागू नई परिभाषा का आम लोग तो कुछ खास अनुभव नहीं कर पायेंगे या यूँ कहें कि आम जन-जीवन में इसके बदलाव में कुछ खास असर नहीं देखा जाएगा पर इसके बदलाव के सुक्ष्मतरंग स्तर पर परिणाम व्यापक होंगे। एसआई की परिभाषा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अंतराष्ट्रीय व्यापार, उच्च तकनीक निर्माण, मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण की

सुरक्षा, वैश्विक जलवायु अध्ययन और बुनियादी विज्ञान के क्षेत्रों में सुलभता आएगी। इससे उच्च स्तर पर प्रकृति के वर्तमान सैद्धांतिक वर्णन के आधार पर इकाइयों को दीर्घकालिक, आंतरिक रूप से आत्मनिर्भर और व्यावहारिक रूप से प्राप्य होने की उम्मीद है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् - सीएसआईआर के महानिदेशक शेखर सी.माडे ने नई इकाइयों की परिभाषा तय करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को बधाई दी है और कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्ट्रूटी 4.0 और अंतरिक्ष में संचार सेवा जैसी भविष्य की कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं। ऐसे में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए इन चुनौतियों से निबटने की तैयारी करना बेहद जरूरी हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय माप विज्ञान समुदाय और विशेष रूप से देश का राष्ट्रीय मापन संस्थान (एनएमआई) इस वर्ष विश्व माप विज्ञान दिवस को एक नई शुरुआत के रूप में मना रहा है। सीएसआईआर और एनपीएल अंतरराष्ट्रीय माप तौल इकाइयों को नए सिरे से परिभाषित किए जाने को व्याख्यानों और कई अन्य कार्यक्रम के जरिए से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। नए सिरे से परिभाषित की गई इन इकाइयों के महत्व को स्वीकार करने और राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचाने दिलाने की जिम्मेदारी के तहत सीएसआईआर और एनपीएल ने नए सिरे से कई दस्तावेज तैयार किए हैं जिनमें माप विज्ञान की पहचान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद् - एनसीआईआरटी, माप विज्ञान में इंजीनियरिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तथा राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम में नयी परिभाषा को समाहित करने के लिए प्रस्तावित बदलाव के सुझाव से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय माप विज्ञान के दिवस के उपलक्ष्य में सीएसआईआर और एनपीएल ने मिलकर 'अंतरराष्ट्रीय माप इकाइयों की नयी परिभाषा और मापविज्ञान से जुड़ी एनपीएल की गतिविधियां' शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। इस पुस्तक में माप इकाइयों की परिभाषा में किए गए बदलावों और भारत की माप विज्ञान अवसंरचना को मजबूत बनाने में एनपीएल की भूमिका की भी विस्तृत जानकारी दी गई है।

गंगा बेसिन क्षेत्र में रुद्राक्ष के वृक्ष लगाने के लिए समझौता ज्ञापन

शिमला/शैल। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के वृक्ष लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, एचसीएल फाउंडेशन और इन्टेक के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों के सहयोग से 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा

शिमला/शैल। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने लोकपाल के सभी सदस्यों की उपस्थिति में लोकपाल की वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एनआईसी की महानिदेशक नीता वर्मा भी उपस्थित थीं। इस वेबसाइट का निर्माण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने किया है और इसमें लोकपाल के संचालन और कार्यपद्धति संबंधी आधारभूत जानकारी प्रदान की गई है।

यह वेबसाइट <http://lokpal.gov.in> पर देखी जा सकती है। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी प्रकार का पहला संस्थान था, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई है। यह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र और सीमा में आने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के

आरोपों की जांच और विवेचना करेगा। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिन्हें 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। सरकार ने इसके साथ ही चार न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की। लोकपाल का अस्थायी कार्यालय वर्तमान में नई दिल्ली स्थित होटल अशोक से कार्यरत है।

लोकपाल के संदर्भ में नियमों को अधिसूचित करने और शिकायत स्वीकार करने के लिए नियमावली की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। 16 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त सभी शिकायतों का लोकपाल कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया और इन्हें निपटाया गया। इस अवधि के पश्चात मिली शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है।

विशाखापत्तनम में कृत्रिम जैव अंगों पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। भारत - ऑस्ट्रेलियाई सहयोग को मजबूत बनाने और दोनों देशों में श्री डी प्रिटिंग उद्योग के विकास के लिए आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्नोलॉजी (एएमटीजेड) द्वारा हाल ही में विशाखापत्तनम में अपने परिसर में कलाम कन्वेंशन सेंटर में जैव अंगों की श्री डी प्रिटिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में प्रयोग में आने वाली तथा नैदानिक और चिकित्सीय उपायों के लिए नए अवसर प्रदान करने वाली एक नवीन तकनीक के रूप में श्री डी प्रिटिंग में मौजूद संभावनाओं की खोज की गई। डायग्नोस्टिक विजुअलाइजेशन से लेकर सर्जिकल प्लानिंग तक श्री डी प्रिटिंग रोगी- विशिष्ट म डल रोगियों और चिकित्सकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ वाली है।

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.जितेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रतिनिधियों को एएमटीजेड में श्री डी प्रिटिंग सुविधा का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि विभिन्न सामग्रियों और विविध अनुप्रयोगों के साथ दुनिया में श्री डी प्रिटिंग सुविधाओं के बड़े केंद्रों में से एक है। उन्होंने श्री डी बायोप्रिटिंग द्वारा कम से कम 10 अंगों को विकसित करने की एक नई पहल - बायो हार्मोनाइज्ड एड्स फॉर रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट (भारत) के बारे में भी बताया। उन्होंने इस परियोजना में अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।

ऊर्जा और स्वास्थ्य में उपयोग के लिए नई सामग्रियों की डिजाइन और

खोज में शामिल ट्रांसलेशनल रिसर्च इनिशिएटिव फॉर सेल्यूलर इंजीनियरिंग एंड प्रिटिंग (टीआरआईसीईपी) के निदेशक डॉ. गार्डन वालेस, ने कार्यशालामें धातु श्री डी प्रिटिंग पर विस्तार से जानकारी दी जो कि श्री डी बायो-प्रिंटेड उत्पादों के लिए सही सामग्री के चयन, फार्मूला तय करने, प्रोटोटाइप का विकास और उनके व्यवसायिकरण के बारे में काफी महत्व रखता है।

सिडनी में एक ओटोलॉजिस्ट और कोक्लियर इंप्लांट तथा स्किल बेस सर्जन के रूप में काम करने वाली और आरएसीएस एनएसडब्ल्यू स्टेड कमेटी की उपाध्यक्ष डॉ. पायल मुखर्जी ने कृत्रिम जैव अंगों पर केवल अनुसंधान ही नहीं बल्कि बड़े जानवरों पर इनके नैदानिक परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने श्री डी प्रिंटेड जैव अंगों के उपयोग में कॉस्मेटिक सर्जनों के सहयोग और भूमिका की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। मद्रास ईएनटी रिसर्च फाउंडेशन (एमईआरएफ), चेन्नई के सलाहकार ईएनटी सर्जन डॉ. रघुनंदन ने श्री डी प्रिंटेड जैव अंगों से जुड़ी शल्य चिकित्सा के लिए सरकारी मदद पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि श्री डी प्रिंटेड जैव अंग कई बार महंगे हो सकते हैं। टीआरआईसीईपी के सहायक निदेशक डॉ. संजय गंभीर (बायो-इंक और बायो मटीरियल्स), स्टार्ट-अप नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के संस्थापक आलोक मेडिकपुरा अनिल और थिंक श्री डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजशेखर उप्पतुरी भी इस कार्यशाला में शामिल हुए।

